वर्षा, सरकारें और मौलिक कर्तव्य

जे. अकलेचा

भारतीय संविधान की धारा 51-एच में वर्णित मौलिक कर्त्तव्यों में भारतीय नागरिकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे 'वैज्ञानिक मिज़ाज और खोज-पड़ताल की भावना का विकास' करेंगे। सवाल यह है कि क्या हमारे शासक भारतीय नागरिक नहीं हैं? अगर हैं तो क्या धारा 51-एच उन पर लागू नहीं होती? सच तो यह है कि शासक होने के नाते उनसे तो संविधान की भावना के अनुरूप चलने की अपेक्षा आम नागरिकों से भी ज़्यादा है। फिर संविधान की यह धारा भी कहती है कि ये कर्त्तव्य केवल नागरिकों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राज्य को भी इनका पालन करना है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? पिछले दो सालों के दौरान जिस तरह से कुछ राज्य सरकारों ने जल प्रबंधन व संरक्षण के वैज्ञानिक तरीकों को दरकिनार कर जल देवता वरुण को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लिया, उससे तो इस सवाल का जवाब नकारात्मक ही मिलता है।

रूठे मानसून को मनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सोम यज्ञों का आयोजन काफी चर्चा में रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र के शोलापुर स्थित श्री योगीराज वेद विज्ञान आश्रम की मदद ली गई। इन आयोजनों के लिए म.प्र. की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने 'पारंपरिक स्वदेशी ज्ञान का प्रमाणीकरण' योजना के तहत लाखों रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की (यह अलग चर्चा का विषय है कि आखिर जनता के टैक्स का पैसा एक विज्ञान संस्था गैर वैज्ञानिक कार्यों पर कैसे खर्च कर सकती है)।

इन सोम यज्ञों का नतीजा क्या निकला? आश्रम ने दावा किया कि पिछले कई वर्षों से सूखे का सामना कर रहे मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 2008 में हुई भारी बारिश इन्हीं सोम यज्ञों का परिणाम थी। यह तो एक तथ्य है कि उस साल बुंदेलखंड में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन अगर यह केवल सोम यज्ञों का ही नतीजा होती तो कम से कम

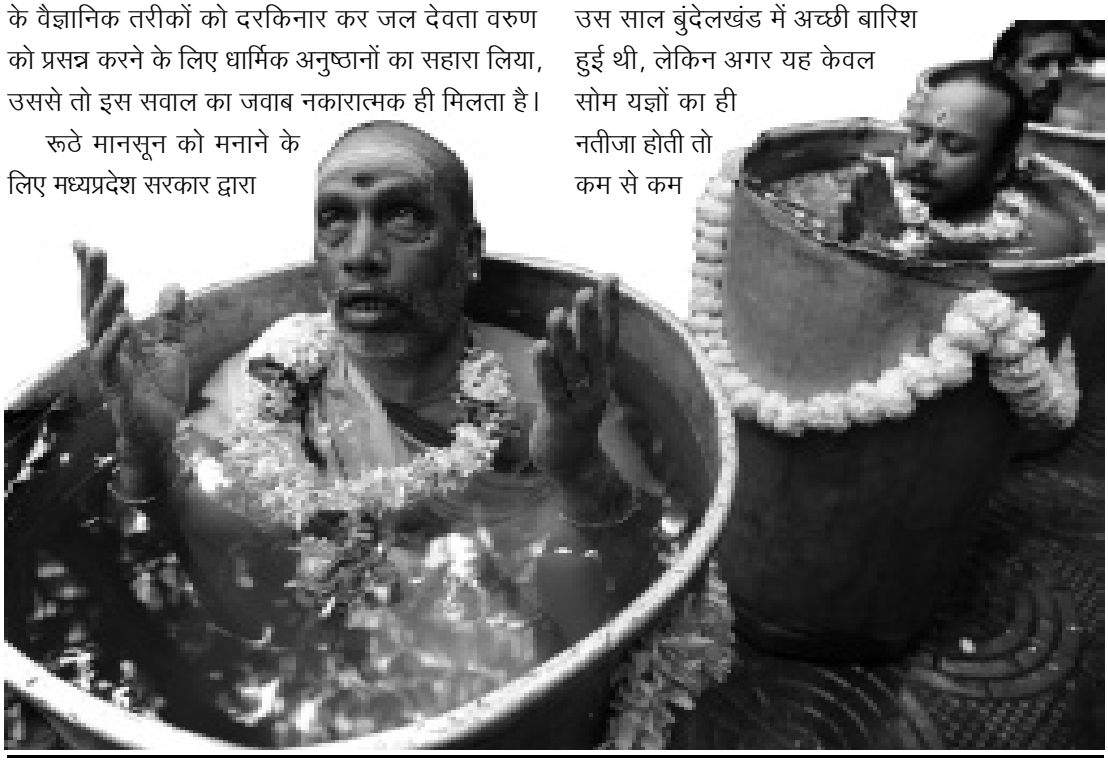

उन सभी स्थलों पर तो सामान्य या सामान्य से बेहतर बारिश होनी चाहिए थी, जहां ये सम्पन्न करवाए गए थे। लेकिन भोपाल स्थित क्षेत्रीय मौसम केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि जिन दस स्थलों (अमरकंटक, छतरपुर, सीधी, सतना, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, उज्जैन और महेश्वर) पर सोम यज्ञों का आयोजन किया गया, उनमें से सात में बारिश सामान्य तो क्या, सामान्य से भी कम हुई। इससे यही साफ होता है कि बारिश का यज्ञों से कोई लेना-देना नहीं है। अगर बुंदेलखंड में उस साल अच्छी बारिश हुई तो यह एक सुखद संयोग ही था, वैसा ही जैसा कि देश के कई क्षेत्रों में होता आया है। यदि सोम यज्ञ इतने ही कारगर होते तो बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज और विशेष दर्जे की ज़रूरत क्या थी? क्यों न इस क्षेत्र के विभिन्न स्थलों पर सोम यज्ञ करवाकर ही बारिश बुलवा ली जाती! बारिश की कमी की वजह से ही यह क्षेत्र लगातार पिछड़ता गया है और इसीलिए इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हाल ही में केंद्र ने 7277 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंज़ूरी दी है।

ऐसा भी नहीं है कि वरुण देवता को मनाने की धार्मिक कवायदें सिर्फ मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने ही की हो। कांग्रेस जैसी मध्यममार्गी पार्टी, जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा भी करती है, भी इसमें पीछे नहीं है। आंध्रप्रदेश के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने पिछले साल (2009 में) 2 से 4 जुलाई के बीच सरकारी खर्च पर तीन दिवसीय 'वरुण यज्ञम' का आयोजन करवाया था। इसका उद्देश्य प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए भगवान वेंकटेश्वर को प्रसन्न करना था।

वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के साथ पिछले कुछ दशकों के दौरान बारिश के पैटर्न में भारी बदलाव आया है। ऐसा नहीं है कि औसत बारिश में कोई विशेष गिरावट आई है, लेकिन वर्षा के दिनों में ज़रूर कमी हुई है। अब कुछ ही घंटों में मूसलाधार बारिश हो जाती है जिससे आंकड़ों में तो वर्षा सामान्य नज़र आती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है और इसी वजह से पानी का संकट लगातार गहराता गया है।

सवाल यह है कि हमारी सरकारें जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती से निपटने के लिए कितनी तैयार हैं। यह एक वृहद समस्या है और इसका समाधान अकेले मध्यप्रदेश या आंधप्रदेश सरकारों के बस के बाहर ही होगा। लेकिन इसकी वजह से मौसम के पैटर्न में आए बदलावों से स्थानीय स्तर पर निपटा जा सकता है, बशर्ते कि हमारे कर्णधार सोम यज्ञ या वरुण यज्ञ जैसे बेमतलब के अनुष्ठानों पर समय और पैसा बर्बाद न करें। इसके लिए सरकारों को वैज्ञानिक तरीकों से जल प्रबंधन करना होगा, व्यापक नीतियां बनानी होंगी और उन पर अमल भी करवाना होगा। कई राज्यों में घरों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करने का नियम पारित हो चुका है, लेकिन इस पर क्रियान्वयन कितना हो पाता है, यह जगज़ाहिर है। सरकार को यदि प्राचीन परंपराओं से इतना ही अनुराग है तो वह जल प्रबंधन के पुराने तरीकों का अनुसरण कर सकती है, जो विज्ञान सम्मत हैं और कारगर भी साबित होंगे। इसके लिए किसी आश्रम के योगियों के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। जल प्रबंधन के कार्य में लगे अनुपम मिश्र और राजेंद्र सिंह जैसे योगियों से सीखा जा सकता है कि सदियों पहले लोग कैसे पानी को सहेजकर रखते थे।

इस तरह के यज्ञों में सरकार के शामिल होने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि आम जनता भी पानी के लिए इसी तरह के यज्ञों व अनुष्ठानों पर और भी ज़्यादा भरोसा करने लगती है। सरकार के स्तर पर क्या यह बेहतर नहीं होगा कि जल प्रबंधन के लिए वे ऐसी मिसालें पेश करें और कार्यक्रम चलाएं कि लोग कल के लिए आज से ही पानी को बचाकर चलें, इतना पानी बचाएं कि कम से कम एक विफल मानसून को हम झेल सकें।

यज्ञों का धार्मिक महत्त्व एक अलग मुद्दा है, लेकिन अच्छा होगा कि इसे व्यक्तिगत आस्था तक ही सीमित रहने दिया जाए और सरकार ऐसे अनुष्ठानों से दूर रहकर जल संरक्षण के ज़मीनी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करे। सरकारों का काम जल प्रबंधन की ऐसी दीर्घकालीन नीतियां बनाना होना चाहिए जिनसे आने वाले सालों में न केवल बारिश की कमी, बल्कि बारिश के पैटर्न में बदलाव से पैदा होने वाली समस्याओं से कारगर ढंग से निपटा जा सके।

जल प्रबंधन के पहले कदम के रूप में सार्वजनिक जल वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जल वितरण के दौरान ही पानी की कितनी बर्बादी होती है, इसके लिए दिल्ली का उदाहरण ही काफी होगा। एक अधिकृत रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को जितना पानी मिलता है, उसका कम से कम 40 फीसदी हिस्सा रिसाव में बर्बाद हो जाता है। अन्य शहरों में स्थिति इससे बेहतर तो शायद ही होगी। लेकिन इस बर्बादी को रोकने के लिए तो कुछ नहीं किया जाता, उल्टे दूर बहती नदियों से शहरों में पानी लाने की योजनाओं पर अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। और जब नदियां भी सूखने लगतीं तो 'भगवान' का ही आसरा रह जाता है।

ग्रीष्म ऋतु की दस्तक हो चुकी है। चूंकि इससे पहले जल प्रबंधन के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया है, इसलिए हर साल की तरह इस बार भी देश के अनेक शहरों में पानी को लेकर वैसा ही हाहाकार मचेगा जैसा पिछले कुछ वर्षों से हर साल मचता आया है। कई जगह शायद खून-खराबा भी होगा। मानसून का मौसम नज़दीक आने के साथ ही बेचैनी भी बढ़ती जाएगी। क्या उम्मीद करें कि अब तो सरकारों के विवेक चक्षु खुलेंगे और वे जल प्रबंधन की दीर्घकालीन योजनाओं पर कार्य करेंगी? ***(स्रोत फीचर्स)***